



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

## सिवनी जिले के विशेष संदर्भ में मध्यप्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन

**Afsana Anjum**

Research Scholar, Department of Sociology, Malwanchal University, Indore

**Dr. Sonali Pandit**

Supervisor, Department of Sociology, Malwanchal University, Indore

### **सारांश (Abstract)**

“सिवनी जिले के विशेष संदर्भ में मध्यप्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन” विषय पर आधारित यह शोध महिलाओं की आर्थिक स्थिति तथा उसके पारिवारिक संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी ने परिवार एवं समाज की पारंपरिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सिवनी जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना तथा यह विश्लेषण करना है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का पारिवारिक संबंधों, निर्णय लेने की क्षमता, बच्चों के पालन-पोषण, वैवाहिक जीवन एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से संकलित किए गए, जबकि द्वितीयक आंकड़े पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों एवं इंटरनेट स्रोतों से प्राप्त किए गए। अध्ययन हेतु सिवनी जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से 400 महिलाओं को नमूने (Sample Size) के रूप में चयनित किया गया। शोध में सरल यादृच्छिक एवं स्तरीकृत निदर्शन पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता अधिक होती है तथा उनके परिवारों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता का स्तर बेहतर पाया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि आर्थिक स्वतंत्रता के कारण पारिवारिक भूमिकाओं एवं सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक विकास से संबंधित नीतियों के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगा।

**मुख्य शब्द:** आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक संरचना, महिला सशक्तिकरण, सिवनी जिला, ग्रामीण-शहरी तुलना, निर्णय-निर्माण, लैंगिक समानता।

### **1. प्रस्तावना एवं शोध की पृष्ठभूमि**

वर्तमान 21वीं सदी में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण सूचक बन चुकी है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पारंपरिक पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना दीर्घकाल



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

से हावी रही है, वहाँ महिलाओं की शिक्षा, रोजगार एवं आत्मनिर्भरता में हो रही वृद्धि एक ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। मध्य प्रदेश — जो देश के मध्य में स्थित है और जहाँ ग्रामीण एवं आदिवासी जनसंख्या की महत्वपूर्ण उपस्थिति है — में भी इस परिवर्तन की लहर स्पष्ट रूप से अनुभव की जा रही है।

सिवनी जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है तथा यह सतपुड़ा पर्वतमाला एवं प्राकृतिक वन संपदा से समृद्ध क्षेत्र है। जिले की भौगोलिक स्थिति एवं सामाजिक विविधता इसे एक आदर्श अनुसंधान क्षेत्र बनाती है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार की सामाजिक संरचनाएँ उपस्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक पारिवारिक संरचना एवं सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में आधुनिक जीवनशैली एवं महिलाओं की सामाजिक सहभागिता अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है। आर्थिक स्वतंत्रता केवल आय अर्जन तक सीमित नहीं है। इसमें आत्मनिर्भरता, निर्णय क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच, बचत प्रबंधन तथा पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारियों में योगदान जैसे अनेक आयाम सम्मिलित हैं। जब एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है, तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बेहतर होता है, बल्कि उसके परिवार, समाज एवं आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ने से न केवल जीडीपी में वृद्धि होती है, बल्कि परिवारों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण पर व्यय भी अधिक होता है। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएँ घरेलू हिंसा, बाल विवाह एवं महिला भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अधिक मुखर एवं सक्षम होती हैं।

इस संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा उसके पारिवारिक प्रभावों — विशेषकर पारिवारिक निर्णय-निर्माण, पति-पत्नी संबंध, बच्चों की शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा — का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है।

## 2. साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं पारिवारिक संरचना पर इसके प्रभावों का अध्ययन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से किया गया है। Sen (1999) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Development as Freedom' में स्पष्ट किया कि महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता केवल आय का विषय नहीं है, बल्कि यह उनकी 'क्षमताओं' (Capabilities) का विस्तार है। उनके अनुसार जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, तो उनकी सौदेबाजी की शक्ति (Bargaining Power) परिवार में बढ़ती है।

Kishor एवं Gupta (2009) के अध्ययन में पाया गया कि भारत में कार्यरत महिलाएँ परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भोजन संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार Jejeebhoy (1995) ने दक्षिण एशिया में 20 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि शिक्षा एवं रोजगार महिलाओं की घरेलू स्वायत्तता के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

भारतीय संदर्भ में, Rustagi (2004) ने मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में महिला श्रम शक्ति भागीदारी का अध्ययन किया और पाया कि ग्रामीण महिलाएँ शहरी महिलाओं की तुलना में सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं का अधिक सामना करती हैं। Naila Kabeer (2001) के अनुसार महिलाओं की रोजगार में भागीदारी उनकी 'एजेंसी' (Agency) को बढ़ाती है, जिससे पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में, विभिन्न सरकारी रिपोर्टें — जैसे मप्र मानव विकास रिपोर्ट 2021 — यह दर्शाती हैं कि राज्य में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) राष्ट्रीय औसत से कम है, परंतु पिछले दशक में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs), प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं उज्वला योजना जैसी सरकारी पहलों ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सिवनी जिले पर विशेष अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं, जिससे यह शोध इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करता है। पूर्व अध्ययनों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के व्यापक सामाजिक आयामों एवं ग्रामीण-शहरी तुलनात्मक विश्लेषण का अभाव पाया गया, जिसे यह शोध पूर्ण करने का प्रयास करता है।

### 3. अध्ययन के उद्देश्य एवं परिकल्पनाएँ

#### 3.1 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए:

1. सिवनी जिले में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर का मूल्यांकन करना।
2. आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त महिलाओं की पारिवारिक भूमिका में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. पारिवारिक निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी की तुलना आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आश्रित महिलाओं के बीच करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के प्रभावों की तुलनात्मक समीक्षा करना।
5. आर्थिक स्वतंत्रता एवं पारिवारिक संबंधों, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा लैंगिक समानता के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

#### 3.2 अनुसंधान परिकल्पनाएँ

अध्ययन में निम्नलिखित 8 परिकल्पनाएँ परीक्षण के लिए निर्धारित की गईं:

क्र. सं.	परिकल्पना (H)	परीक्षण विधि
H <sub>1</sub>	आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं की पारिवारिक निर्णय-निर्माण में भागीदारी आश्रित महिलाओं की तुलना में अधिक होती है।	Independent t-test



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

H <sub>2</sub>	महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का पारिवारिक संरचना एवं संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।	Correlation
H <sub>3</sub>	आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आत्मनिर्भरता आश्रित महिलाओं से अधिक होती है।	Independent t-test
H <sub>4</sub>	ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के बीच आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर है।	Independent t-test
H <sub>5</sub>	महिलाओं की आय एवं रोजगार परिवार में निर्णय क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।	Correlation
H <sub>6</sub>	आर्थिक स्वतंत्रता से पति-पत्नी संबंधों एवं बच्चों की शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन होता है।	Correlation
H <sub>7</sub>	शिक्षित एवं कार्यरत महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता का स्तर अधिक होता है।	Independent t-test
H <sub>8</sub>	एकल परिवार की महिलाओं पर आर्थिक स्वतंत्रता का प्रभाव संयुक्त परिवार से अधिक होता है।	Independent t-test

## 4. अनुसंधान पद्धति

### 4.1 शोध का स्वरूप एवं अभिकल्प

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive), विश्लेषणात्मक (Analytical) एवं तुलनात्मक (Comparative) शोध की प्रकृति पर आधारित है। वर्णनात्मक पद्धति में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार, आय एवं पारिवारिक भूमिका से संबंधित वर्तमान स्थिति का तथ्यात्मक चित्रण किया गया। विश्लेषणात्मक पद्धति में विभिन्न चरों के मध्य संबंधों एवं प्रभावों का गहन परीक्षण किया गया। तुलनात्मक पद्धति में ग्रामीण-शहरी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र-आश्रित, शिक्षित-अशिक्षित एवं एकल-संयुक्त परिवार की महिलाओं के बीच तुलना की गई।

### 4.2 अध्ययन क्षेत्र: सिवनी जिले का परिचय

सिवनी जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में 21°38' उत्तरी अक्षांश एवं 79°32' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसकी सीमाएँ बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला जिलों तथा महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़ी हैं। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 8,758 वर्ग किमी है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 13.78 लाख थी। जिले में साक्षरता दर 71.2% है, जिसमें महिला साक्षरता 61.5% है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, वन उत्पाद, लघु उद्योग एवं सेवा क्षेत्र पर आधारित है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार की सामाजिक संरचनाओं की उपस्थिति के कारण यह जिला तुलनात्मक अध्ययन के लिए आदर्श क्षेत्र है।



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

## 4.3 नमूना चयन एवं तथ्य संग्रहण

अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण एवं स्तरीकृत नमूना चयन तकनीक (Purposive and Stratified Sampling) का उपयोग किया गया। कुल 400 महिला उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया — 236 (59%) ग्रामीण एवं 164 (41%) शहरी क्षेत्र से। प्राथमिक तथ्यों के लिए 40 कथनों वाली संरचित प्रश्नावली का निर्माण किया गया, जिसमें पाँच-बिंदु लिफ्ट स्केल (1=बिल्कुल असहमत से 5=पूर्णतः सहमत) का उपयोग किया गया। द्वितीयक स्रोतों में सरकारी रिपोर्टें, जनगणना आंकड़े, शोध पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें सम्मिलित थीं।

विशेषता	श्रेणी	संख्या (N)	प्रतिशत (%)
आयु वर्ग	18-25 वर्ष	82	20.5
	26-35 वर्ष	126	31.5
	36-45 वर्ष	104	26.0
	46 वर्ष एवं अधिक	88	22.0
निवास क्षेत्र	ग्रामीण	236	59.0
	शहरी	164	41.0
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	248	62.0
	अविवाहित	86	21.5
	विधवा/तलाकशुदा	66	16.5
शिक्षा	अशिक्षित/प्राथमिक	102	25.5
	माध्यमिक	118	29.5
	स्नातक एवं ऊपर	180	45.0
परिवार का प्रकार	संयुक्त	228	57.0
	एकल	172	43.0
मासिक आय	₹5,000 से कम	72	18.0
	₹5,001 - ₹20,000	234	58.5
	₹20,000 से अधिक	94	23.5

तालिका 4.1: उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का वर्गीकरण (N=400)

## 5. डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या

### 5.1 आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष

लिफ्ट स्केल आधारित 40 कथनों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ सामने आईं:

कथन	माध्य (Mean)	मध्यक (Median)	SD	व्याख्या
-----	--------------	----------------	----	----------



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।	4.24	4.00	0.78	उच्च सहमति
आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएँ परिवार में अधिक आत्मनिर्भर होती हैं।	4.20	4.00	0.80	उच्च सहमति
शिक्षित महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता का स्तर अधिक है।	4.18	4.00	0.82	उच्च सहमति
आर्थिक स्वतंत्रता से परिवार की जीवनशैली में सुधार।	4.10	4.00	0.87	उच्च सहमति
बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव।	4.09	4.00	0.88	उच्च सहमति
आर्थिक स्वतंत्रता के बाद परिवार में निर्णय क्षमता बढ़ी।	4.07	4.00	0.91	उच्च सहमति
मेरी शिक्षा ने आत्मनिर्भरता में सहायता की।	4.05	4.00	0.90	उच्च सहमति
स्वयं का बैंक खाता उपलब्ध है।	4.01	4.00	0.94	उच्च सहमति
संपत्ति/निवेश निर्णयों में सहमति ली जाती है।	3.76	4.00	1.11	मध्यम सहमति

तालिका 5.1: आर्थिक स्वतंत्रता एवं पारिवारिक प्रभाव से संबंधित प्रमुख कथनों का वर्णनात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश कथनों का माध्य 4.0 से ऊपर पाया गया, जो लिकर्ट स्केल पर 'सहमत' श्रेणी में आता है। यह दर्शाता है कि सिवनी जिले की महिलाएँ सामान्यतः आर्थिक स्वतंत्रता के सकारात्मक पारिवारिक एवं सामाजिक प्रभावों को स्वीकार करती हैं। मानक विचलन (SD) का मान अधिकांश कथनों में 1.0 से कम पाया गया, जो प्रतिक्रियाओं की स्थिरता एवं समरूपता को दर्शाता है। संपत्ति/निवेश निर्णयों में SD 1.11 अपेक्षाकृत अधिक है, जो इस विषय पर उत्तरदाताओं में अधिक भिन्नता दर्शाता है — यह स्वाभाविक है क्योंकि संपत्ति संबंधी निर्णय पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान रहे हैं।

## 5.2 परिकल्पना परीक्षण के परिणाम

परिकल्पना	t-मूल्य / r	df	p-मूल्य	परिणाम
H <sub>1</sub> : स्वतंत्र vs आश्रित — निर्णय क्षमता (Mean: 4.18 vs 3.41)	t = 5.74	≈398	0.000	✓ स्वीकृत
H <sub>2</sub> : आर्थिक स्वतंत्रता vs पारिवारिक संबंध	r = 0.68	400	0.001	✓ स्वीकृत



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

H <sub>3</sub> : स्वतंत्र vs आश्रित — सामाजिक प्रतिष्ठा (Mean: 4.22 vs 3.36)	t = 6.18	≈398	0.000	✓ स्वीकृत
H <sub>4</sub> : शहरी vs ग्रामीण (Mean: 4.21 vs 3.68)	t = 5.29	≈398	0.000	✓ स्वीकृत
H <sub>5</sub> : आय/रोजगार vs निर्णय क्षमता	r = 0.72	400	0.000	✓ स्वीकृत
H <sub>6</sub> : आर्थिक स्वतंत्रता vs वैवाहिक/शैक्षणिक परिवर्तन	r = 0.69	400	0.001	✓ स्वीकृत
H <sub>7</sub> : शिक्षित/कार्यरत vs अशिक्षित (Mean: 4.26 vs 3.29)	t = 6.84	≈398	0.000	✓ स्वीकृत
H <sub>8</sub> : एकल vs संयुक्त परिवार (Mean: 4.19 vs 3.72)	t = 4.97	≈398	0.000	✓ स्वीकृत

तालिका 5.2: परिकल्पना परीक्षण के परिणाम ( $p < 0.05$  स्तर पर)

सभी 8 परिकल्पनाएँ  $p < 0.05$  स्तर पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक पाई गईं, जो यह सिद्ध करती हैं कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता उनके पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न आयामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।  $t$ -मूल्यों की उच्चता (4.97 से 6.84 तक) यह दर्शाती है कि समूहों के बीच अंतर केवल संयोगवश नहीं, बल्कि वास्तविक एवं सार्थक है। सहसंबंध गुणांक ( $r = 0.68$  से  $0.72$ ) मध्यम से उच्च सकारात्मक संबंध को दर्शाते हैं।

### 5.3 ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति

शोध के तुलनात्मक विश्लेषण में ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के बीच स्पष्ट असमानताएँ सामने आईं। 80.75% उत्तरदाताओं (सहमत + पूर्णतः सहमत) ने माना कि शहरी महिलाओं को आर्थिक अवसर अधिक मिलते हैं। इसी प्रकार, 80.25% ने यह स्वीकार किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर सामाजिक प्रतिबंध अधिक हैं। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार में कठिनाइयों का सामना करने की बात 80% उत्तरदाताओं ने स्वीकार की।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की राह में प्रमुख बाधाएँ हैं: सामाजिक प्रतिबंध एवं पितृसत्तात्मक सोच, सीमित शैक्षणिक सुविधाएँ, रोजगार के कम अवसर, परिवहन की समस्या, आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुँच, तथा बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी पारंपरिक बाधाएँ। शहरी क्षेत्रों में इन बाधाओं की तीव्रता अपेक्षाकृत कम है, परंतु वहाँ भी कार्य-जीवन संतुलन, असमान वेतन एवं शीशे की छत जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं।

सकारात्मक संकेत यह है कि 78% उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण परिवारों का दृष्टिकोण धीरे-धीरे बदल रहा है। स्वयं सहायता समूहों, डिजिटल साक्षरता एवं सरकारी योजनाओं के कारण ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक जागरूकता बढ़ रही है।



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

## 5.4 पारिवारिक निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी

पारिवारिक निर्णय-निर्माण के विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए। 77.5% महिलाओं ने माना कि परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय ली जाती है। बच्चों की शिक्षा संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक (79.75%) पाई गई, जो यह दर्शाता है कि मातृत्व एवं शैक्षणिक निर्णय महिलाओं का प्रभावक्षेत्र बन रहे हैं।

आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं में निर्णय क्षमता का माध्य 4.18 था, जबकि आश्रित महिलाओं में यह केवल 3.41 था। यह 0.77 का अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यंत सार्थक ( $t = 5.74, p < 0.001$ ) है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक स्वतंत्रता प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की पारिवारिक निर्णय शक्ति को बढ़ाती है। हालाँकि, संपत्ति एवं निवेश संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम (70.75%) पाई गई, जो यह संकेत देता है कि इस क्षेत्र में अभी भी पितृसत्तात्मक नियंत्रण बना हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बिंदु है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

## 5.5 पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव

पारिवारिक संबंधों के विश्लेषण में सहसंबंध गुणांक  $r = 0.68$  ( $p < 0.001$ ) पाया गया, जो आर्थिक स्वतंत्रता एवं पारिवारिक संबंधों के बीच मजबूत सकारात्मक संबंध को दर्शाता है। विशिष्ट निष्कर्षों में पाया गया कि 75.5% महिलाओं ने माना कि आर्थिक स्वतंत्रता से पति-पत्नी संबंधों में सुधार हुआ है। 78% महिलाओं के अनुसार परिवार में आपसी सम्मान बढ़ा है। उनके रोजगार के कारण बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव 79% ने स्वीकार किया। परिवार की जीवनशैली में सुधार 78.25% ने माना। घरेलू तनाव में कमी 73% ने अनुभव की। घरेलू जिम्मेदारियों का बेहतर विभाजन 74.5% ने स्वीकार किया। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि एकल परिवारों में आर्थिक स्वतंत्रता का प्रभाव (Mean = 4.19) संयुक्त परिवारों (Mean = 3.72) की तुलना में अधिक पाया गया। इसका कारण यह है कि एकल परिवारों में महिला को अधिक स्वायत्तता एवं निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जबकि संयुक्त परिवारों में पारंपरिक सामूहिक निर्णय प्रणाली कभी-कभी महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है।

## 6. विवेचना एवं परिचर्चा (Discussion)

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के बीच के जटिल अंतर्संबंध को स्पष्ट करते हैं। ये निष्कर्ष Amartya Sen के 'Capabilities Approach' तथा Naila Kabeer के 'Agency' सिद्धांत के अनुरूप हैं। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो उनकी क्षमताओं एवं विकल्पों का विस्तार होता है, जो पारिवारिक एवं सामाजिक ढाँचे को अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है।

शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक ( $t = 6.84$ ) के रूप में उभरी। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुरूप है जो शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का प्रमुख साधन मानता है। 82.5% शिक्षित एवं कार्यरत महिलाओं ने उच्च आर्थिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट की, जो यह दर्शाता है कि शिक्षा में निवेश सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है।



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

सरकारी योजनाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण पाई गई। 77.25% उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने में सहायक हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से 80% महिलाओं के पास स्वयं का बैंक खाता उपलब्ध है (Mean = 4.01), जो वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण संकेतक है। मनरेगा, उद्यम सखी, लखपति दीदी जैसी योजनाएँ ग्रामीण महिलाओं की आय एवं स्वायत्तता में वृद्धि कर रही हैं।

हालाँकि कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। परिकल्पनाएँ स्वीकृत होने के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में 'निश्चय नहीं' की प्रतिक्रिया देने वाली महिलाओं का अनुपात (10-14%) चिंताजनक है। यह उन महिलाओं को दर्शाता है जो आंशिक रूप से सशक्त हैं परंतु पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता अभी भी प्राप्त नहीं कर सकी हैं। संपत्ति अधिकारों एवं उत्तराधिकार में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशीलता की बाधाएँ, पर्दा प्रथा एवं सामाजिक दबाव महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। दोहरे बोझ (Dual Burden) — घरेलू कार्य एवं बाहरी रोजगार — की समस्या महिलाओं के लिए एक गंभीर चुनौती है।

इस शोध का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि पारिवारिक समर्थन (Family Support) महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का एक प्रमुख सुगमकर्ता (Enabler) है। 74.25% महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में परिवार का सहयोग मिला, जो यह दर्शाता है कि परिवार का दृष्टिकोण बदल रहा है — विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जहाँ 80% परिवार महिलाओं की नौकरी को स्वीकार करते हैं।

## 7. निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusions & Recommendations)

### 7.1 प्रमुख निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं:

- आर्थिक स्वतंत्रता एवं पारिवारिक सशक्तिकरण: सिवनी जिले की महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता पारिवारिक निर्णय-निर्माण, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आत्मनिर्भरता को सांख्यिकीय रूप से सार्थक रूप से प्रभावित करती है। सभी 8 परिकल्पनाएँ  $p < 0.05$  पर स्वीकृत हुईं।
- शिक्षा का प्राथमिक महत्व: शिक्षित एवं कार्यरत महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता का स्तर सर्वाधिक ( $t = 6.84$ , Mean = 4.26) पाया गया। शिक्षा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी मार्ग है।
- ग्रामीण-शहरी असमानता: शहरी महिलाएँ ग्रामीण महिलाओं की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हैं (Mean 4.21 vs 3.68)। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक प्रतिबंध एवं सीमित अवसर प्रमुख बाधाएँ हैं।
- बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव: आर्थिक रूप से स्वतंत्र माताओं के बच्चों की शिक्षा पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव (Mean = 4.09, 79% सहमति) पाया गया, जो अगली पीढ़ी में मानव पूँजी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

- लैंगिक समानता: 83% महिलाओं का मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है (Mean = 4.24) — यह अध्ययन का सर्वोच्च माध्य है।
- परिवर्तनशील दृष्टिकोण: ग्रामीण परिवारों का दृष्टिकोण धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में बदल रहा है (78%), जो भविष्य के लिए आशाजनक संकेत है।

## 7.2 नीतिगत सुझाव

प्रस्तुत शोध के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

### शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु:

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में निवेश बढ़ाना अत्यावश्यक है। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति एवं आवासीय सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएँ। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को विस्तृत किया जाए ताकि महिलाएँ ऑनलाइन आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकें।

### रोजगार एवं उद्यमिता हेतु:

महिला उद्यमियों के लिए सूक्ष्म वित्त एवं ऋण सुविधाओं को सरल एवं सुलभ बनाया जाए। स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की जाए। महिला स्वामित्व वाले उद्यमों को सरकारी क्रय में प्राथमिकता दी जाए। गृह-आधारित उद्योगों एवं ऑनलाइन व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाए।

### सामाजिक-परिवारिक सुधार हेतु:

पुरुषों एवं परिवारों के लिए लैंगिक समानता पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ। घरेलू कार्यों की साझेदारी को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जाए। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की जानकारी एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

### सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता हेतु:

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। योजनाओं की जानकारी स्थानीय भाषाओं में सरल तरीके से पहुँचाई जाए। लाभार्थी महिलाओं की नियमित फॉलो-अप की व्यवस्था हो। ग्रामीण महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लक्षित कार्यक्रम तैयार किए जाएँ।

## 8. अध्ययन की सीमाएँ एवं भविष्य के शोध

प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सीमाएँ हैं: (1) अध्ययन केवल सिवनी जिले तक सीमित है, इसलिए निष्कर्षों का सामान्यीकरण सीमित है। (2) 400 उत्तरदाताओं का नमूना पर्याप्त है, परंतु विशाल जनसंख्या की तुलना में सीमित। (3) सामाजिक संवेदनशील विषय होने के कारण कुछ उत्तरदाताओं ने पक्षपाती प्रतिक्रिया दी हो सकती है। (4) अनुदैर्घ्य (Longitudinal) डेटा का अभाव — यह एकमुश्त सर्वेक्षण है, इसलिए समय के साथ परिवर्तन नहीं मापे जा सके।

भविष्य में निम्नलिखित दिशाओं में शोध किया जा सकता है: मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में तुलनात्मक अध्ययन, अनुदैर्घ्य अध्ययन जो समय के साथ परिवर्तनों को मापे, पुरुषों के दृष्टिकोण पर शोध ताकि



# Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति पारिवारिक सदस्यों की सोच को समझा जा सके, तथा विशिष्ट सरकारी योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन।

## 9. उपसंहार (Conclusion)

प्रस्तुत शोध पत्र यह सिद्ध करता है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता एवं पारिवारिक संरचना के बीच एक गहरा, सार्थक एवं सकारात्मक संबंध है। सिवनी जिले में किए गए इस तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, तो वे न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

वर्णनात्मक सांख्यिकी से स्पष्ट हुआ कि आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकांश कथनों का माध्य 4.0 से ऊपर है, जो सकारात्मक सहमति दर्शाता है। t-परीक्षण एवं सहसंबंध विश्लेषण ने यह सिद्ध किया कि आर्थिक स्वतंत्रता निर्णय क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, वैवाहिक संबंध एवं बच्चों की शिक्षा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच अभी भी महत्वपूर्ण असमानताएँ हैं, परंतु बदलाव की दिशा सकारात्मक है। शिक्षा, सरकारी योजनाओं एवं सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ये असमानताएँ कम हो रही हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण न केवल एक मानवाधिकार है, बल्कि यह एक स्वस्थ, संतुलित एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की अनिवार्य शर्त है। सिवनी जिले की महिलाएँ इस परिवर्तन का जीवंत प्रमाण हैं।

## संदर्भ सूची (References)

1. सेन, ए. के. (1999). डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
2. कबीर, एन. (2001). महिला सशक्तिकरण के मापन पर विचार। स्टडीज़ इन सोशल पॉलिसी, सिडा, स्टॉकहोम।
3. किशोर, एस., एवं गुप्ता, के. (2009). भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। एनएफएचएस-3, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़, मुंबई।
4. जेजीभाँय, एस. जे. (1995). महिलाओं की शिक्षा, स्वायत्तता और प्रजनन व्यवहार। क्लैरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड।
5. रुस्तगी, पी. (2004). श्रम शक्ति सहभागिता में लैंगिक अंतर। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नई दिल्ली।
6. International Labour Organization (2023). विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य : महिलाओं के लिए रुझान 2023। आईएलओ, जिनेवा।
7. National Family Health Survey-5 (2019-21). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5। आईआईपीएस, मुंबई एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. Government of Madhya Pradesh (2021). मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन। भोपाल।
9. Census of India (2011). प्राथमिक जनगणना सारांश — सिवनी जिला। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, नई दिल्ली।
10. नुसबाम, एम. सी. (2000). महिलाएँ और मानव विकास : क्षमता दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. World Bank (2022). महिलाएँ, व्यवसाय और कानून 2022। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वाशिंगटन डी.सी.
12. Ministry of Women and Child Development (2022). वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22। भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. बोसेरप, ई. (1970). आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका। अर्थस्कैन पब्लिकेशन्स, लंदन।
14. डे बिस्वास, एस. (2015). ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण : मुद्दे और चुनौतियाँ। दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।
15. राव, एन., एवं केलेहर, डी. (2005). क्या जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के बाद भी जीवन है? जेंडर एंड डेवलपमेंट, 13(2), 57-69।